“स्वतंत्रता के 70 साल: क्या पाया और क्या पाना बाकी है” विषय पर सेमिनार

विजन इंडिया रिसर्च सेंटर द्वारा 2017 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिसार में “स्वतंत्रता के 70 साल: क्या पाया और क्या पाना बाकी है” विषय पर सेमीनार आयोजित किया गया। सेमिनार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जातिवाद, संप्रदायिकता तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य इन सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ सरकार व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करना था। इसके पीछे इन समस्याओं को हल करने में आम जनता को सक्रिय करने का भी यह एक प्रयास था। विजन इंडिया रिसर्च सेंटर के चेयरमैन डॉ. दलबीर भारती की देखरेख में हुए इस सेमिनार में प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं लेखिका डॉ. शमीम शर्मा, दयानंद महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. महेंद्र सिंह, एडवोकेट श्री लाल बहादुर खोवाल, सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता सर्वश्री. विजेंद्र संभ्रवाल, जोगीराम खुंडिया व उदयभान चौपड़ा ने विभिन्न विषयों पर उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन श्री. भूपेंद्र प्रजापति ने की।

अपने संबोधन में डॉ. शमीम शर्मा ने विस्तार से बताया कि प्राचीन काल से ही महिलाओं पर अत्याचार होते आये हैं। उन्होनें यह स्वीकार किया कि देश आजाद होने के बाद पिछले 70 साल में महिलाओं कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, महिलायें उच्च व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके लगभग सभी क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियां करने लगी हैं। निजी व्यवसायों एवं कारपोरेट सेक्टर में भी महिलाओं की भागीदारी बढी है। इस प्रकार से पिछले 70 साल में महिलाओं ने शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। परंतु महिलाओं ने इस प्रगति के साथ साथ उनके साथ होने वाले भेदभाव एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं किया। डॉ. शमीम शर्मा ने कहा कि महिलाओं ने घूंघट तो उतार दिया परंतु उस घूँघट का झंडा नहीं बनाया। उन्होनें महिलाओं से आह्वान किया कि वे ना केवल शिक्षा व रोजगार पर ध्यान दें बल्कि महिला वर्ग के प्रति लोगों के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ आंदोलन भी करें।

प्रो. महेन्द्र सिंह ने पिछले 70 साल में भारत में हुई सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंनें कहा कि राजनीतिक स्वतत्रंता एवं अधिकारों के क्षेत्र में पिछले 70 साल में अच्छी प्रगति हुई है। आज हर वर्ग एवं स्तर का व्यक्ति गांव, जिला, राज्य तथा देश स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परंतु इस प्रजातांत्रिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है।

विजेंद्र संभ्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद पिछले 70 साल में, विशेषकर संविधान लागू होने के बाद से, समानता एवं स्वतत्रंता के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के अथक प्रयत्नों से देश को एक अच्छा संविधान प्राप्त हुआ। परंतु कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों एवं वर्गों ने संविधान में निहित समानता, स्वतत्रंता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों को अमल में लाने से मना कर दिया। इस वजह से जातिवाद और सांप्रदायिकता ने समाज में अपना नियत्रंण बनाए रखा और भारतीय समाज को सही मायने में एकजुट नहीं होने दिया। उन्होंनें कहा कि डॉ. आम्बेडकर के दिखाये रास्ते का अनुसरण करते हुए जातिवाद एवं सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए हमारे देश में बहुत कुछ करना बाकी है।

एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि पिछले 70 साल में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। देश भर में असख्ंय स्कूल एवं उच्च शिक्षा के संस्थान खोले गये हैं। आज हर राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैंनेजमैंट, इत्यादि विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय उपलब्ध हैं। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले 70 साल में कई गुना बढी है। कृषि, पशुपालन, विधि, विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय खोले गये हैं। परंतु जिस गति से शिक्षा के अवसर बढे हैं उस गति से शिक्षित युवाओं को योग्य रोजगार देने में हमारा देश पीछे रह गया है। आज लाखों की संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त युवा बेरोजगार हैं। इसलिए हमारे देश व राज्यों की सरकारों ने बढती हुई बेरोजगारी पर नियत्रंण पाने तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

जोगीराम खुंडिया ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश में शहरों, कस्बों एवं गांवों में बहुत विकास हुआ है। जहां 70 साल पहले गावों में अधिकतर लोग कच्चे मकानों में रहते थे, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी, गांव की गलियां कच्ची थी, मुख्य मार्ग पर नहीं पड़ने वाले गांव सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे। अधिकतर गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। बहुत से गांवों में प्राथमिक शिक्षा से आगे शिक्षा की सुविधा नहीं थी तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवायें भी गांवों में उपलब्ध नहीं थी। पिछले 70 सालो में केन्द्र सरकारों ने पंचवर्षिय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के उपरोक्त क्षेत्रों मे बहुत विकास किया है। इसी प्रकार कस्बों एवं शहरों में भी बहुत विकास हुआ है। सड़कें, विकसित आवसीय परिसर, होटल, रेस्टोरेंन्ट, मनोरजंन के साधन, इत्यादि क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। परंतु इसके साथ साथ छोटे कस्बों और शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों एवं मलिन बस्तियों की सख्यां भी बढी है। गांवों में शौचालयों, स्वच्छ पानी एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अभी भी कमी है। इस प्रकार से पिछले 70 साल में ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा गरीबी मिटाने की दिशा में काफी प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

उदयभान चौपड़ा ने भारत की मानव विकास सूचकांक की तुलना अन्य देशों से की। उन्होंने आंकड़ों सहित बताया कि बहुत से क्षेत्रों में भारत ने पिछले 70 साल में प्रगति की है परंतु मानव संसाधन विकास पर जहां अन्य देश प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं उनकी तुलना में हमारे देश में बहुत कम खर्च किया जाता है. इसी कारण मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में भारत अन्य देशों के मुकाबले में बहुत पीछे है। इस दिशा मे बहुत कुछ करना बाकी है।

डॉ. दलबीर भारती ने सेमिनार का समापन करते हुए कहा कि संविधान में प्रदान किए हुए व्यक्ति के सभी मौलिक एवं अन्य अधिकारों को सही मायने मे लागू करने के लिए समाज के सभी वर्गों को सहयोग करना चाहिये. जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा देश जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव जैसी समस्याओं को हल नहीं कर पायेगा। उन्होंनें लोगों को जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर आपसी विश्वास, सहयोग एवं सामाजिक सद्भाव बनाने पर जोर दिया। डॉ. भारती ने यह भी कहा कि विजन इंडिया रिसर्च सेंटर भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हुए सामाजिक और राष्ट्र की समस्याओं की ओर सरकारों और लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। सेमिनार में बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग के पुरुष, महिलाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। सेमिनार के आयोजन में सर्वश्री इंद्राज भारती, सज्जन ढोकवाल, रतन बड़गुज्जर व श्रवण भार्गव ने सहयोग किया।

*****